

राज्य वधियकों पर राज्यपाल की शक्तियाँ

प्रलिस के लयल:

राज्य वधियकों पर राज्यपाल की शक्तलयाँ, सर्वोच्च नयायालय (SC), संवधलन का अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, संवधलन का अनुच्छेद 31A

मेन्स के लयल:

राज्य के वधियकों, सरकारी नीतलयाँ तथा वधलनलन कषेत्रों में वकलस के लयल हस्तकषेप और उनकी रूपरेखा तथा कारयानवयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर राज्यपाल की शक्तलयाँ

[स्रोत: द हदु](#)

चरुा में कयों?

हाल ही में भारत के [सर्वोच्च नयायालय \(SC\)](#) ने कहा है कलजब राज्यपाल कसलसी वधियक पर सहमतल रोकता है तो उसके लयल [संवधलन के अनुच्छेद 200](#) में उल्लखलतल वशलषलट काररवाई का पालन करना अनवलरय है ।

- अनुच्छेद 200 का मुख्य पहलू यह है कल यह राज्यपाल को सहमतल रोकने के अपने कारणों के बारे में सूचतल करने तथा वधलनमंडल को वधियक पर पुनरुवलचार करने के लयल प्रेरतल करने का आदेश देता है ।

सर्वोच्च नयायालय का नरलणय कया है?

- यदल कलई राज्यपाल कसलसी वधियक को मंजूरी देने से इनकार करता है, तो उसे [अनुच्छेद 200](#) का अनुपालन करना होगा ।
- सर्वोच्च नयायालय ने माना है कल यदल कलई [राज्यपाल कसलसी वधियक पर सहमतल रोकने का फैसला करता है](#) तो उसे वधियक को पुनरुवलचार के लयल वधलयकल को वापस करना होगा ।
- वधियक के पुनरुमूल्यांकन के लयल वधलनमंडल की आवश्यकता को संप्रेषतल करने के आवश्यक कदम के बनल राज्यपाल द्वारा सहमतल को रोकना [संवैधानकल सलधलतों का उल्लंघन](#) है ।
- वधियक पर अंतलम नरलणय नरलवाचतल वधलयकल का होता है तथा राज्यपाल का संदेश उन्हें सहमत होने के लयल बाध्य नहीं करता है । अरुथात् एक बार जब [सदन लौटाए गए वधियक को संशोधन के साथ अथवा बनल संशोधन के दोबारा पारतल कर देता है तो राज्यपाल के पास सहमतल देने के अतरलकत कलई वकलल्प नहीं होता है ।](#)
- कसलसी वधियक को [सुवीकार करने अथवा असुवीकार करने का अंतलम अधकलर नरलवाचतल वधलनमंडल के पास](#) है एवं राज्यपाल का संदेश वधलयी नकलय को बाध्य नहीं करता है ।

वधलयकों पर राज्यपाल की शक्तलयाँ कया हैं?

- **अनुच्छेद 200:**
 - भारतीय संवधलन का अनुच्छेद 200 कसलसी राज्य की वधलनसभा द्वारा पारतल वधियक को सहमतल के लयल [राज्यपाल के समकष प्रसुतुत करने की प्रकरयल को रेखांकतल करता है](#), जो या तो सहमतल दे सकता है, सहमतल को रोक सकता है या राष्ट्रपतल द्वारा वधलयक के लयल वधियक को आरकषतल कर सकता है ।
 - राज्यपाल सदन या सदनों द्वारा पुनरुवलचार का अनुरोध करने वाले संदेश के साथ [वधियक को वापस भी कर सकता है ।](#)
- **अनुच्छेद 201:**
 - इसमें कहा गया है कलजब कलई वधियक राष्ट्रपतल के वधलयक के लयल आरकषतल होता है, तो [राष्ट्रपतल वधलयक पर सहमतल दे सकता है या उस पर रोक लगा सकता है ।](#)
 - राष्ट्रपतल वधलयक पर पुनरुवलचार करने के लयल राज्यपाल को उसे सदन या राज्य के वधलनमंडल के सदनों को वापस भेजने का नरलदेश भी दे सकता है ।

■ राज्यपाल के पास उपलब्ध वकिलप:

- वह राष्ट्रपति के विचार हेतु विधायक को आरक्षण कर सकता है। आरक्षण अनिवार्य है जहाँ राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधायक राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है। हालाँकि राज्यपाल विधायक को आरक्षण भी कर सकता है यदि यह नमिनलिखित प्रकृति का हो:
- एक अन्य वकिलप सहमति को रोकना है, लेकिन ऐसा सामान्य रूप से किसी भी राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता है क्योंकि यह एक अत्यंत अलोकप्रिय कार्यवाही होगी।
 - संविधान के प्रावधानों के खिलाफ
 - **राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP)** का विरोध
 - देश के व्यापक हित के खिलाफ
 - गंभीर राष्ट्रीय महत्त्व का
 - संविधान के अनुच्छेद 31A के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो।
- वह सहमति दे सकता है या विधायक के कुछ प्रावधानों या विधायक पर स्वयं पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हुए इसे विधानसभा को वापस भेज सकता है।

क्या राज्यपाल विधायकों की शक्तियों का प्रयोग कर किसी विधायक पर सहमति रोक सकता है?

- जबकि **अनुच्छेद 200** को पढ़ने से पता चलता है कि राज्यपाल अपनी सहमति रोक सकता है, विशेषज्ञों का सवाल है कि क्या वह केवल मंत्रपरिषद की सलाह पर ही ऐसा कर सकता है।
- संविधान में प्रावधान है कि राज्यपाल अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग **अनुच्छेद 154 के तहत मंत्रपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है।**
- बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा द्वारा विधायक पारित होने पर राज्यपाल को सहमति रोकने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिये।

लंबित विधायकों से जुड़ी समस्याएँ क्या हैं?

- **नरिणय लेने में देरी:**
 - विधायिका द्वारा पारित विधायकों पर नरिणय लेने में राज्यपाल की **वफिलता से नरिणय लेने में देरी होती है**, जो राज्य सरकार के प्रभावी कार्यकरण को प्रभावित करती है।
 - जब राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधायक पर नरिणय लेने में वफिल रहता है, तो **इससे नीतियों और कानूनों के कार्यान्वयन में देरी होती है।**
- **लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करना:**
 - राज्यपाल, जसि केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, राजनीतिक कारणों से राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधायकों को वलिंबित या असवीकार करने के लिये अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है।
- **लोक धारणा:**
 - आम लोग प्रायः राज्यपाल के पास लंबित विधायकों को राज्य सरकार की अक्षमता या उसके भ्रष्टाचार के संकेत के रूप में देखते हैं, जो सरकार की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचा सकता है।
- **उत्तरदायित्व की कमी:**
 - राज्यपाल अपनी सहमति रोकने के नरिणय का कारण बताने के लिये बाध्य नहीं है।
 - उत्तरदायित्व की यह कमी शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को कमजोर करती है।

Governor

Eligibility Criteria

- Must be a **citizen of India**
- At least **35 years** of age
- Must **not be a member of (either) house** of Parliament/State Legislature
- Must not hold any **office of profit**

Appointment and Tenure (Part VI)

- Appointed by President (**Article 153**)
- One person can be appointed as Governor for **2+ States (7th Const. Amendment in 1956)**
- Holds the office at the **Pleasure of the President** (maximum **5 years**)

Powers (Part VI)

- Article 161: **Pardoning powers**
- Article 164: Power to **appoint the CM and other Ministers**
- Article 176: **Special Address** by Governor
- Article 200: Power to **(withhold) assent/reserve a bill** (Legislative Assembly)
- Article 213: Power to **promulgate Ordinances**

'Dual Capacity'

- **Constitutional head of the state** and **Representative of the Union government**

Ending Tenure before 5 Years

- **Dismissal by President** (on advice of the Council of Ministers headed by PM)
 - Dismissal of governors without a valid reason is not permitted
- On grounds of **acts upheld by courts as unconstitutional** and malafide
- **Resignation** by the governor

Responsibilities

- **Appoints** – CM, other Ministers, Advocate General of State, Members of State PSC, judges of HC and districts
- Act as **ex-officio chancellor** of state Universities

- राज्यपालों को **अनुच्छेद 200 के दशा-नरिदेशों** का पालन करना चाहिये, वधियकों के वषिय में अपनी चतिाओं को तुरंत बताना चाहिये और उन्हें पुनरुवचिार के लयि राज्य वधिानसभा को वापस भेजना चाहिये। यह एक उचति प्रकुरयिा सुनशिचति करता है और वधिानसभा के अधकिार का सम्मान करता है।
- स्पष्ट दशिा-नरिदेश और पारदर्शी प्रकुरयिाएँ **गलतफहमी से बचने में मदद कर सकती हैं**। कसिी वधियक पर सहमतारोकते समय **राज्यपालों को** अपने नरिणयों के लयि जवाबदेही सुनशिचति करते हुए **पारदर्शी तरक प्रदान करना चाहिये**।
- वधिायी प्रकुरयिा में राज्यपालों की भूमकिा पर नरितर चरुा और कानूनी स्पष्टता प्रकुरयिाओं को और भी अधकि सुव्यवस्थति कर सकती है तथा संभावति संघरुषों से बच सकती है।

कानूनी अंतरदृष्टतः [COI का अनुच्छेद 200](https://www.drishtijudiciary.com/hin)

<https://www.drishtijudiciary.com/hin>

UPSC सविलि सेवा परीकषा, वगित वरुष के प्ररुशुन

??????????:

प्ररुशुन. पुनमिनलखिति में से कौन-सी कसिी राज्य के राज्यपाल को दी गई वविकाधीन शकुरतयिाँ हैं? (2014)

1. भारत के राष्ट्रपतको राष्ट्रपतशिासन अधरिीपति करने के लयि रपिरुट भेजना।
2. मंतरुयिों की नयुकुतरा करना। राज्य वधिानमंडल द्वारा पारति कतपिय वधियकों को भारत के राष्ट्रपतके वचिार के लयि आरकषति करना।
3. राज्य सरकार के कारुय संचालन के लयि नयिम बनाना।

नीचे दयि गए कूट का प्ररुयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- संवधिान के अनुच्छेद 163 में कहा गया है किराज्यपाल अपने वविक की आवश्यकता वाले कारुयों को छोडकर अपने कारुयों को मंतरुपरिषिद की सहायता और सलाह से करेगा।
- भारतीय संवधिान के अनुच्छेद 356 के तहत कसिी राज्य का राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपतशिासन लगाने की सफिराशि करते हुए भारत के राष्ट्रपतको एक रपिरुट भेज सकता है। यह राज्यपाल को प्रदतुत एक वविकाधीन शकुरत है। **अतः 1 सही है।**
- वह मुखुयमंतरुी (CM) और अन्य मंतरुयिों की नयुकुतरा करता है। वे उसकी इच्छानुसार पद पर भी बने रहते हैं। राज्य मंतरुमिंडल में मंतरुयिों की नयुकुतरा राज्यपाल के वविक पर नहीं होती है। वह केवल औपचारकि रूप से नयुकुतराको मंजूरी देता है। वविक मुखुयमंतरुी के अधीन आता है **अतः 2 सही नहीं है।**
- राज्यपाल राज्य वधिानमंडल द्वारा पारति कूछ वधियकों को राष्ट्रपतके वचिार के लयि आरकषति कर सकता है। एक मामले में ऐसा आरकषण अनविरुय है, अरुथात् जहाँ राज्य वधिायकिा द्वारा पारति वधियक राज्य उचुच नुयायालय की स्थतिको खतरे में डालता है। इसके अलावा राज्यपाल वधियक को आरकषति भी कर सकता है यदयिह संवधिान के प्रावधानों के खलिाफ है, राज्य के नीतनिदिशक सदिधांतों के वपिरित है, देश के व्यापक हति के खलिाफ है, गंभीर राष्टुरीय महतुत्व का है आदि। **अतः 3 सही है।**
- वह राज्य सरकार के व्यवसाय के अधकि सुवधिाजनक लेन-देन और उकत व्यवसाय के मंतरुयिों के बीच आवंटन के लयि नयिम बनाता है। लेकनि यह शकुरतरा राज्यपाल के वविक के अधीन नहीं है। वह मंतरुपरिषिद की सलाह पर कारुय करता है। **अतः 4 सही नहीं है।**
- **अतः वकिलप (b)सही उत्तर है।**